>

Title: Need to conduct the audit of the Ministries, Departments and Semi-Government undertakings by the Government Institutions instead of any private or non-Government institutions.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): महोदय, एफडीआई जो नया इंट्रोडयूज़ किया है, उसके मार्फत बहुत सारी विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तान की कंपनियों में पैसा लगा रही हैं। लेकिन कुछ गाइड लाइन्स ऐसी हैं और जो तकलीफ उनके सामने बहुत जबरदस्त तरीके से आ रही है कि बाहर की कुछ कंपनियां 10-15 परसेंट पैसा लगाती हैं, इक्विटी शेयर खरीदती हैं, उसके द्वारा वे उस कंपनी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोफिट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके प्रोफिट्स को लोन में बदलने की कोशिश करते हैं। उस पर कंपाउंड इंटरस्ट लगाकर उसे थर्ड पार्टी को बेच देते हैं। फिर उस कंपनी को बेचने की या उस पर पूरी तरह हावी होने की, या कंट्रोल करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं और इसके कई मामले सामने आए हैं। हिन्दुस्तान का एक दैनिक पेपर है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह का कुठाराघात किया और जिसकी चिट्ठी भी मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखी थी। मैं यह चाहता हूँ कि इसमें कुछ गाइडलाइन्स हैं जो सरकार को ज़रूर बनानी चाहिए।

1. whether the exit price as foreign investors mentioned in their Investment Agreements, i.e., minimum assured return of 25 per cent – 40 per cent compound interest on dollar terms, is in consonance with the RBI guidelines and FIPB approval for FDI for equity investment;

2. whether the same would convert the nature of equity investment to External Commercial Borrowing;

3. whether the affirmative voting rights as Investors mentioned in the Investment Agreements violate sectoral cap of 26 per cent, if any, in that sector;

4. whether they are in contravention of RBI guidelines, FDI policy, the Companies Act and the approval letters of FIPB where no such disclosures and/or permissions sought/given and they control Indian companies through minority shares;

5. whether the in-built options or supported by options sold by third parties in the Investment Agreement would lose their equity character as envisaged in the Companies Act 1956;

6. whether they violate Indian FDI laws and norms;

7. whether the same would convert the nature of investment to debt and what shall be the impact of such equity investments in India that have such fixed returns if they are all treated as debt instead of equity? What shall be the impact of such debt on the sovereign credit rating of the country?

मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि वह इस पर कदम उठाकर इसकी कुछ गाइडलाइन्स जल्दी से जल्दी बनवा दें ताकि इंडियन कंपनीज़ सेफ रहें।